

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *202
31 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

इस्पात का उत्पादन

*202. श्री के. अशोक कुमार:

डॉ. किरिट पी. सोलंकी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या अगले 14 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत इस्पात उत्पादन क्षमता में और 182 मिलियन टन की वृद्धि किए जाने संबंधी सरकार की महत्वाकांक्षा के पूरी होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या गत दशक के दौरान इस्पात उत्पादन क्षमता में मात्र 60 मिलियन टन की वृद्धि हुई है तथा इस्पात की स्थिर मांग के कारण इस क्षेत्र की ऋण स्थिति खराब हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कई वैश्विक इस्पात उत्पादकों ने इस कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और कच्चे माल के लिए ढुलाई की समस्या के कारण विभिन्न हरित क्षेत्र इस्पात परियोजनाओं को त्याग दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और
- (ङ) देश में इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

इस्पात के उत्पादन के बारे में श्री के. अशोक कुमार एवं डॉ. किरिट पी. सोलंकी, संसद सदस्यों द्वारा लोक सभा में दिनांक 31 जुलाई, 2017 को उत्तर देने के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *202 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां। अप्रैल-जून 2017-18 के दौरान भारत में कूड इस्पात के उत्पादन के आंकड़े गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.5% की वृद्धि को इंगित करते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	कूड इस्पात का उत्पादन (एमटी)
अप्रैल-जून 2016-17*	23.72
अप्रैल-जून 2017-18*	24.56
% बदलाव	3.5
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम; एमटी=मिलियन टन	

(ख): मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भारत की कूड इस्पात क्षमता 126 मिलियन टन है। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017, में घरेलू कूड इस्पात की क्षमता को वर्ष 2030-31 तक बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई है। इसे नीचे दर्शाया गया है, जिससे यह इंगित होता है कि वर्ष 2016-17 (अनंतिम) की तुलना में अगले 14 वर्षों में क्षमता में 174 मिलियन टन की वृद्धि होगी।

वर्ष	कूड इस्पात की क्षमता (एमटी)
अप्रैल-जून 2016-17*	126.33
अप्रैल-जून 2030-31^	300
वृद्धि	173.67
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम, ^एनएसपी 2017 के अनुसार अनुमानित	

(ग): वर्ष 2007-08 से 2016-17 के दौरान 66.49 मिलियन टन कूड इस्पात क्षमता बढ़ाई गई है। इस अवधि के दौरान घरेलू फिनिशड इस्पात की खपत 6% सीएजीआर (कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) की दर से बढ़ी है और इसलिए, इस्पात क्षेत्र की इस वित्तीय स्थिति के कारण को इस्पात की मांग में स्थिरता से नहीं जोड़ा जा सकता। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान इस्पात वस्तुओं की कीमतों में अधिक गिरावट होने और पूर्ण फिनिशड इस्पात के आयातों में वृद्धि (71%) होने के कारण इस्पात कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(घ) और (ड): इस्पात परियोजना को स्थापित करने का निर्णय व्यक्तिगत निवेशक द्वारा विभिन्न घटकों जैसे कि भूमि की स्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता, परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता, लॉजिस्टिक, इत्यादि के आधार पर लिया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट, 2015 और कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2015 लागू किया है। इस सांविधिक कार्य ढांचे में लौह अयस्क और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए पारदर्शी तरीका अपनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 8 मई, 2017 को राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 जारी की है, जिसमें भारतीय इस्पात उद्योग के दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार ने सरकारी खरीद में 'घरेलू निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) को प्राथमिकता' प्रदान करने की एक नीति को भी अधिसूचित किया है, जिससे इस्पात क्षेत्र में घरेलू मांग, उत्पादन और मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी।
